

भारतीय विदेश नीति एवं पड़ोसी प्रथम की नीति पर हिन्द महासागरीय राजनीति का प्रभाव

डॉ. नियाज अहमद अन्सारी

सारांश

अप्रैल 2025 में थाईलैंड में सम्पन्न हुए बिस्मटेक के 6 वें शिखर सम्मेलन में हिन्द महासागर से जुड़े भारत एवं अन्य तटीय देशों के मध्य आपसी व्यापार के साथ ही सामुद्रिक सुरक्षा का प्रश्न भी छाया रहा। विश्व के तीसरे सबसे बड़ा महासागर के रूप में हिन्द महासागर वर्तमान भू-राजनीति के केन्द्र में आता जा रहा है। इस महासागर ने हमेशा न केवल भारत की सामुद्रिक सुरक्षा की है, बल्कि अन्तराष्ट्रीय व्यापार और सांस्कृतिक संबन्धों को भी मजबूत किया है। इसका क्षेत्रफल 74 मिलियन वर्ग किलोमीटर है और वर्तमान में इसके तटवर्ती देशों की संख्या 40 है। यह महासागर **एशिया, अफ्रीका और आस्ट्रेलिया** तीन महाद्वीपों से घिरा हुआ है। पृथ्वी के सम्पूर्ण जलमंडल के 20 प्रतिशत भाग पर इसका विस्तार है।¹ अन्तराष्ट्रीय राजनीति में यह महासागर भू-राजनीतिक दृष्टि से सदैव चर्चित बना रहा है। आज भारत का लगभग 70 प्रतिशत तेल का आयात और 90 प्रतिशत अन्तराष्ट्रीय व्यापार इसके जलमार्ग से ही होता है। अतः हिन्द महासागरीय क्षेत्र में स्थायी शांति एवं सुरक्षा बनी रहने पर ही भारत अपने राष्ट्रहितों की पूर्ति हेतु इसका पूर्ण दोहन करके अपनी विकास यात्रा को सुरक्षा एवं व्यापार हेतु निर्बाध रूप से जारी रख सकता है। भारत ने 2023 में जी-20 के 17वें सम्मेलन की अध्यक्षता सफलतापूर्वक करके विश्वभर को ' **वसुधैव कुटुम्बकम्** ' की अवधारणा से परिचित कराकर **एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य** (*One Earth, One Family & One Future*) का प्रेरक सन्देश दिया है।

* सहा. आचार्य: राजनीति शास्त्र एवं व्यक्तित्व विकास, शासकीय आदर्श महाविद्यालय, उमरिया (म. प्र.),
पिन- 484661 ई-मेल: dr.ansaari786@gmail.com

वास्तव में, भारतीय ज्ञान परम्परा में प्राचीनकाल से ही **विश्व कल्याण,विश्व शांति, सहअस्तित्व,जियो और जीने दो,अहिंसा परमो धर्मः,योग-निरोग,सर्वधर्म-समभाव** आदि मानवीय मूल्यों को संरक्षित और प्रचारित किया है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में हिन्द महासागर को ' **रत्नाकर** ' कहा गया है। **आचार्य कौटिल्य (चाणक्य)** के अर्थशास्त्र में षाणगुण नीति और मण्डल सिद्धांत में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास पर भी विवेचन हुआ है।³ जैसाकि आधुनिक युग में **हेन्स जे मारगेनथाउ ने *Politics Among Nations*** में प्रयास किया है।

दुर्भाग्यवश,समकालीन भौतिक विकास,उदारीकरण और भूमंडलीकरण ने मानव को जहां एक तरफ अर्थोमुखी,आरामपरस्त और विलासी बनाया है तो दूसरी तरफ स्वार्थी एवं अर्थोन्मुखी बनाकर जनकल्याण के मार्ग से भटका दिया है। अब भारतीय राजनयिकों,व्यवसायी-उद्यमियों, युवा राष्ट्रसेवकों, शिक्षकों, राजनेताओं आदि सभी वर्ग के लोगों को अपनी-अपनी सशक्त भूमिका निभानी होगी, तभी हम हिन्द महासागरीय क्षेत्र में स्थायी शांति एवं सुरक्षा बनी रहने पर अपने राष्ट्रहितों की पूर्ति हेतु इसका पूर्ण दोहन कर पाएंगे और भारतीय विदेश नीति एवं पड़ोसी प्रथम की नीति को हिन्द महासागरीय राजनीति के माध्यम से भारतीय हितों की पूर्ति की जा सकती है।

कुंजी शब्द- हिन्द महासागर, भारतीय विदेश नीति, विकसित भारत, हिमतक्षेस एवं आपसी क्षेत्रीय सहयोग।

भारत ने 2023 में जी-20 के 17वें सम्मेलन की अध्यक्षता सफलतापूर्वक करके विश्वभर को '**वसुधैव कुटुम्बकम्**' की अवधारणा से पुनः परिचित कराकर **एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य** का प्रेरक सन्देश दिया है। वास्तव में, भारतीय ज्ञान परम्परा में प्राचीनकाल से ही **विश्व कल्याण, विश्व शांति, सहअस्तित्व, जियो और जीने दो,अहिंसा परमो धर्मः, योग-निरोग, सर्वधर्म-समभाव** आदि मानवीय मूल्यों को संरक्षित और प्रचारित किया है। आचार्य कौटिल्य (चाणक्य) की षाणगुण नीति और मण्डल सिद्धांत में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास पर व्यापक विवेचन किया गया है। इसलिए भारत संयुक्त राष्ट्र की विकास यात्रा में भी सक्रिय सहयात्री बनकर विभिन्न सकारात्मक एवं सहयोगात्मक भूमिकाओं में अपना

योगदान सुनिश्चित करता आ रहा है। आज भी मानव अधिकारों के संरक्षण, सुरक्षा परिषद सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लोकतांत्रिकरण, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद के उन्मूलन एवं संघर्षरत क्षेत्रों में शांति बहाली की दिशा में लगातार प्रयासरत बना हुआ है। अतः समकालीन वैश्विक राजनीति में भारतीय विदेश नीति की बढ़ती महत्ता एवं प्रभावोत्पादकता एवं हिन्द महासागरीय क्षेत्र में सामने खड़ी चुनौतियों एवं उपलब्ध भावी उज्ज्वल संभावनाओं की विवेचना निम्नवत बिन्दुओं में करना समीचीन होगा-

1. भारत के लिए हिन्द महासागर का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व
2. हिन्द महासागर का बढ़ता आर्थिक एवं भू-राजनीतिक महत्व
3. विकसित भारत 2047 के लिए सामरिक और आर्थिक रणनीति
4. सतत विकास हेतु लक्ष्योन्मुखी नीति
5. हिमालय एवं दक्षिण एशिया में भारत की बढ़ती भूमिका
6. हिन्द महासागर में महाशक्तियों की उपस्थिति और भारत की चिंताएं

1. भारत के लिए हिन्द महासागर का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व

—

पूर्व विदेश सचिव जे. एन. दीक्षित ने अपनी पुस्तक 'भारतीय विदेश नीति' में लिखा है- " आधुनिक भारत में राजा राममोहन राय पहले भारतीय रहे हैं जिन्होंने भारत को विश्व के साथ जोड़ने की जरूरत अनुभव की थी । उन्होंने अपने मित्र जेरेमी बेंथम को भारत के विभिन्न विभागों में सुधार प्रक्रिया को तेज करने हेतु कई पत्र लिखे थे " भारत द्वारा वैश्विक एवं पड़ोसी संबंध, अंतर्निष्ठ शोध, सशक्त अर्थव्यवस्था, आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा, क्षेत्रीय सहयोग, बहुध्रुवीयता का विस्तार, पर्यावरण संरक्षण, सुशासन आदि क्षेत्रों में अर्जित उपलब्धियों ने देश का सम्मानीय स्थान दिलाया है ।

प्राचीन भारत के नौसेना विशेषज्ञ **भोजदेव जी** ने भारत को विश्व के साथ जोड़ने के लिए **हिन्द महासागर** पर ध्यान देने की बात कही है । इसलिए 4 से 6 वीं सदी में मौर्य एवं आंध्र क्षेत्र के राजवंशों ने बंगाल की खाड़ी में सामुद्रिक एकाधिकार स्थापित कर **मलाया, जावा, सुमात्रा** आदि क्षेत्रों में उपनिवेश स्थापित किए थे । 11 वीं सदी में

दक्षिण भारत के चोल एवं चालुक्य राज्यों और 1803 में हुए **ट्रेफाल्गर युद्ध** में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराकर हिन्द महासागर पर प्रभाव स्थापित किया था । 1946 में अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में पं. जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा कहा था, “ हमारा सदैव यह प्रयत्न होगा कि हमारी विदेश नीति का संचालन राष्ट्रहितों की पूर्ति और विश्व की शांति एवं सुरक्षा में सामंजस्य बनाकर किया जाए । ”

2. हिन्द महासागर का भू-राजनीतिक महत्व और विकसित भारत –

उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने तो 1970 से ही इसके **डिएगो गारसिया द्वीप** में अपना सैन्य अड्डा बना रखा है । पिछले 3 दशकों से अमेरिका, चीन और रूस जैसी महाशक्तियां इसकी खनिज सम्पदा के अधिकतम दोहन के लिए गिद्ध दृष्टि लगाए हुए हैं । अमेरिकी नौसेना के विशेषज्ञ **अल्फ्रेड मॉहन** ने भविष्यवाणी की थी, “ **जो भी देश हिन्द महासागर पर नियंत्रण कर सकेगा, वही एशिया पर अपना वर्चस्व भी स्थापित करेगा ।** ”

21वीं सदी के प्रारंभिक एक-तिहाई दशक में भारत ने न केवल राष्ट्रीय, बल्कि विश्व मंच पर अनेक क्षेत्रों में उपलब्धियां अर्जित की हैं, जैसे- **मजबूत और विश्वस्नीय होते विदेश संबंध, अंतर्निक्षेप शोध में उत्कृष्ट प्रगति, विकासोन्मुखी अर्थव्यवस्था, चाक-चौबंद सुरक्षा, क्षेत्रीय सहयोग, सूचना प्रौद्योगिकी, बहुध्रुवीयता, उत्कृष्ट नेतृत्व, पर्यावरण संरक्षण, सफल भू-राजनीति** आदि । आज भारत ने अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने और भारत के पुनरुत्थान के लक्ष्य अर्थात् **विकसित भारत- 2047** की ओर तेजी से अग्रसर बनी हुई है । इसलिए भारतीय विदेश नीति की वर्तमान भूमिका को विश्व मंच पर लगातार सराहा जा रहा है । हिन्द महासागर के बढ़ते लगातार आर्थिक एवं भू-राजनीतिक महत्व ने भारतीय विदेश नीति की बढ़ती महत्ता एवं प्रभावोत्पादकता को विश्व स्तर पर सराहा भी जा रहा है । उल्लेखनीय है कि इस महासागर में **सोना, हीरा, मैंगनीज, जिंक, टंगस्टन , बॉक्साइट, क्रोमियम और यूरेनियम सहित पेट्रोलियम पदार्थों** की विपुल संभावनाओं के कारण महाशक्तियां कई दशकों से गिद्ध दृष्टि लगाए हुए हैं । उल्लेखनीय है कि इस महासागर में विश्व का 90 प्रतिशत रबड़, 85 प्रतिशत हीरा, 80 प्रतिशत सोना, 70 प्रतिशत टिन, 60 प्रतिशत यूरेनियम, 37 प्रतिशत तेल , 28 प्रतिशत मैंगनीज, 27 अ

क्रामियम, 16 प्रतिशत लोहा, 12 टंगस्टन, 11 प्रतिशत निकल, 10 प्रतिशत जिंक आदि पाये जाने की संभावनाएं पायी गई हैं ।

3. विकसित भारत 2047 के लिए सामरिक और आर्थिक रणनीति-

भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पर 5 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है । यह विश्व पटल पर अनोखी चमक की तरह उभरी है जो कि राज्य सरकारों एवं केन्द्र सरकार के मूलतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकास की ओर अधिक बल देने के सकारात्मक प्रयासों का परिणामों की उपज है । भारत की सैंकड़ों योजनाएं अब भारत को अत्मनिर्भर बनाने में सहायक साबित हो रहीं हैं । इसके लिए सरकारों द्वारा देश की उन्नति हेतु ग्रामीण स्तर पर लघु, कुटीर एवं अन्य उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु यथासंभव प्रयास किए जा रहे हैं । **भारतीय अर्थव्यवस्था के विकासात्मक निष्पादन को देखकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक एवं भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2024-25 में भारत की आर्थिक विकास दर 7 प्रतिशत से अधिक रहने का अनुमान लगाया है।** चूंकि अभी भारत विकासशील देश है, परंतु यह छोटे-बड़े उद्योग की सहायता के साथ-साथ उद्यमियों की प्रगति से भी विकसित देश बनने की ओर तेजी से अग्रसर बना हुआ है । इस दिशा में हिन्द महासागर की महती भूमिका को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता ।

4. सतत् विकास हेतु लक्ष्योन्मुखी नीति-

20वीं सदी में शीतयुद्ध के कारण संयुक्त राष्ट्र ज्यादातर समय निष्प्रभावी एवं अप्रसांगिक ही बना रहा है जिसके कारण विश्व के हर महाद्वीप में विभिन्न देशों के आपसी संघर्ष चरम पर पहुंच चुके हैं और विश्व शांति की स्थापना धूमिल एवं असम्भव दिखाई दे रही है। अतः अब शीतयुद्ध की समाप्ति एवं 21वीं सदी के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित किए गए प्रमुख सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) की व्यापकता एवं इनको प्राप्त करने हेतु यह अत्यंत जरूरी हो गया कि अब भारत अपनी विदेश नीति को हिन्द महासागर पर केन्द्रित कर आगे बढ़ता रहे । उल्लेखनीय है कि भारत की 7516 किलोमीटर लम्बी विशाल तटरेखा में 13 बड़े एवं 200 छोटे बन्दरगाह स्थित हैं। उल्लेखनीय है कि राजनयिक के. एम. पनिकर ने अपनी पुस्तक

Problems of Indian Defence में लिखा है, " सुरक्षा और विदेश नीति में अटूट सम्बंध होता है जिसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है । भारत में औद्योगिक एवं वाणिज्यिक विकास तब तक संभव नहीं है जबतक हिन्द महासागर पर भारत का प्रभावी नियंत्रण स्थापित नहीं होता ।"

5. हिमतक्षेस एवं दक्षिण एशिया में भारत की बढ़ती भूमिका –

भारत की विदेश नीति में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में उल्लिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर भारत ने बहुत ही आस्था एवं विश्वास के साथ अपनाकर 1997 में **हिमतक्षेस संगठन** का गठन नेल्सन मंडेला की पहल पर किया गया था । **हिमतक्षेस** का पूर्ण रूप है- हिन्द महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन । वर्तमान में इसके 22 देश सदस्य और 12 वार्ता भागीदार देश हैं। इसका मुख्यालय मॉरीशस में है । 2004 में आयी सुनामी में राहत गतिविधियों और 2008 में एंटी पाइरेसी गतिविधियों पर रोक जगाने और 2020 से 2022 की अवधि में कोरोला महामारी के समय इस क्षेत्र में अपनी नौसैनिक उपस्थिति भी दर्ज कराई थी ।

भारत ने अपनी विदेश नीति के माध्यम से हमेशा अपनी भूमिका को इस संगठन के मूल उद्देश्यों से जोड़कर सहयोगात्मक काम किया है –

अ. हिमतक्षेस क्षेत्र सहित विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना ।

आ. सदस्य राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्ण संबंधों और भाईचारा की भावना का संचार करना ।

इ. द्विपक्षीय एवं बहुराष्ट्रीय विवादों को अंतर्राष्ट्रीय समुद्रीय कानूनों द्वारा निराकृत करना।

ई. अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण वार्ताओं और सौहार्द की भावना से हल करना।

6. भारत के लिए महाशक्तियों की चिंताजनक उपस्थिति-

अमेरिका सहित रूस और चीन जैसी महाशक्तियों की हिन्द महासागर में उपस्थिति भारत के लिए **चिंताजनक बनी रही है** । जहां अमेरिका ने **डिएगो गारसिया द्वीप**

में अपना सैन्य अड्डा बना रखा है, वहीं चीन अपनी **मोतियों की माला नीति** अर्थात् **Strings of Pearls Policy** के तहत चीन ने हांगकांग से सूडान तक श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, सोमालिया, सूडान के दर्जनभर बंदरगाहों को गिरवी रखकर या अपने ऋणजाल में फंसाकर अपने हितों की पूर्ति में लगा हुआ है। उल्लेखनीय है कि चीन की यह नीति हिन्द महासागर क्षेत्र में चीनी महत्वांक्षा संबंधी मीडिया जनित भू-राजनीतिक सिद्धांत है जो इस महासागर की समुद्रीय रेखाओं पर वाणिज्य के नाम पर चीनी सेना और संबंधों के नेटवर्क को प्रकट करता है।

उल्लेखनीय है कि चीन का यह बढ़ता सामरिक नेटवर्क भारत की सुरक्षा एवं समृद्धि के लिए अनेक संकट उत्पन्न करता आ रहा है। व्यापार एवं शोध के नाम पर चीन ने हिन्द महासागर क्षेत्र में अनेक जगह अपने टोही पोतों को भी तैनात कर रखा है। भारत के पड़ोसी देशों के- **कोको द्वीप (म्यांमार), चटगांव (बांग्लादेश) हम्बनटोटा (श्रीलंका), गुवादर (पाकिस्तान)** आदि बन्दरगाहों को चीन गिरवी रखकर या ऋणजाल में फंसाकर लगभग हड़प चुका है।

इस महासागर की समुद्रीय सीमाओं और समुद्री डकैती को लेकर भारत की ये चिंताएं बनी हुई हैं-

1. इस क्षेत्र से मिलनेवाले **पेट्रोलियम पदार्थों** का अधिकतम दोहन करके अरब देशों से आयात निर्भरता को कम करना।
2. सोना, हीरा, मैगनीज, जिंक, टंगस्टन, बॉक्साइट, क्रोमियम, यूरेनियम आदि खनिजों का भरपूर उत्खनन करके आयात निर्भरता को कम करके देश की ऊर्जा और औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
3. अमेरिका, रूस और चीन जैसी महाशक्तियों की हिन्द महासागर पर क्रियाशील कूटनीतियों से भारतीय हितों की रक्षा कर पाना।

निष्कर्ष

अतः विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनकर भारत के पुनरूत्थान के लक्ष्य- **विकसित भारत- 2047** की ओर तेजी से अग्रसर बने रहने में हमारी भारतीय विदेश नीति प्रभावशील बनी रह सकती है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रूस के कजान शहर में अक्टूबर 2024 को आयोजित ब्रिक्स के 16 वें शिखर सम्मेलन में अन्तराष्ट्रीय राजनीति में भारत की उज्ज्वल संभावनाओं को इन शब्दों में व्यक्त किया है, “ अब भारत के पास कृषिगत व्यापार, ई-कामर्स, आपसी क्षेत्रीय सहयोग, सूचना प्रौद्योगिकी, विशेष आर्थिक क्षेत्रों, अंतरिक्ष शोध आदि दर्जनभर क्षेत्रों में परस्पर सहयोग करने के अवसरों की भरपूर उपलब्धता है । ”

वर्तमान वैश्विक राजनीति में भारतीय विदेश नीति की बढ़ती महत्ता, प्रभावोत्पादकता एवं भावी उज्ज्वल संभावनाओं की उपर्युक्त शोधपरक विवेचना के आधार पर निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारतीय ज्ञान परम्परा ने प्राचीनकाल से ही विश्व को लोक कल्याण, विश्व शांति, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्मः , योग-निरोग, सर्वधर्म-समभाव आदि मानवीय मूल्यों को संरक्षित और प्रचारित किया है। समकालीन भौतिक एवं तकनीकी विकास, उदारीकरण और भूमंडलीकरण ने मानव को जहां एक तरफ आरामपरस्त और विलासी, स्वार्थी एवं अर्थोन्मुखी बनाकर जनकल्याण के मार्ग से भटकाया है तो दूसरी ओर विकास की नूतन आशाओं का भी संचार किया है। अब भारतीय राजनयिकों, व्यवसायी-उद्यमियों, युवा राष्ट्रसेवकों, शिक्षकों, राजनेताओं, शोधकर्ताओं आदि सभी को अपनी-अपनी सशक्त भूमिका निभानी होगी, तभी हम अपनी ज्ञान परम्परा, गौरवपूर्ण इतिहास एवं प्राकृतिक सम्पदाओं का संरक्षण और समुचित दोहन कर पाएंगे। भारत के राजनयिक के. एम. पत्रिकर ने कई बार कहा है, “ हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि भारत का अस्तित्व और भविष्य हिन्द महासागर पर केन्द्रित रहेगा । ” अतः भारतीय विदेश नीति की प्रमुख उपनीतियों पड़ोसी प्रथम की नीति एवं पूर्व की ओर देखो नीति आदि को हिन्द महासागरीय राजनीति के माध्यम से भारतीय हितों की पूर्ति की जाकर विश्व राजनीति में भारत अपनी सशक्त भूमिका का निर्वहन किया जा सकता है ।

संदर्भ ग्रंथ

अन्सारी, नियाज अहमद , संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में भारत का योगदान, ज्ञान गरिमा सिन्धु , अक्टूबर-दिसम्बर 2020, अंक-68 , वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली, पृ. 208

ओझा, विवेक, भारत की आंतरिक सुरक्षा : चुनौतियां और समाधान , 2020, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 133

ओझा, विवेक, समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंध, 2020, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 392

कुमार,अशोक, भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां, 2024, मैकग्रा हिल एजुकेशन (इंडिया) प्रा. लि., चैन्नई , पृ. 10.29

दीक्षित,जे.एन. , भारतीय विदेश नीति, 2018, प्रभात पेपरबैक्स, नई दिल्ली, पृ. 15

पॉडैय,बाबूराम, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, 2008, प्रकाश बुक डिपो, बरेली, पृ. 197

प्रतियोगिता दर्पण, दिसम्बर 2024, उपकार प्रकाशन, आगरा, पृ. 15

प्रतियोगिता दर्पण, फरवरी 2025, उपकार प्रकाशन, आगरा, पृ. 145

प्रतियोगिता दर्पण, सितम्बर 2024, उपकार प्रकाशन, आगरा, पृ. 25

फडिया, बी.एल. , अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, 2018, साहित्य भवन, आगरा, पृ. 458

भारद्वाज,रामदेव,भारत एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध,2018, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, पृ. 466

भारद्वाज,रामदेव,भारत एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध,2018, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, पृ. 468

मिश्रा,राजेश, भारतीय विदेश नीति : भूमंडलीकरण के दौर में, 2019, ओरियंट ब्लैकस्वान प्रा.लि., हैदराबाद, पृ. 121

श्रीवास्तव, सी.बी.पी. , भारत और विश्व : बदलते परिदृश्य , 2002, किताब महल, नई दिल्ली, पृ. 49

सिंह , बाल्मीकी प्रसाद, 21 वीं सदी : भूराजनीति, लोकतंत्र और शांति , 2024, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास , नई दिल्ली, पृ. 121

सीकरी,राजीव, भारत की विदेश नीति : चुनौती और रणनीति, 2017,सेज पब्लिकेशंस इंडिया प्रा.लि. , नई दिल्ली, पृ. 252